भारत-चीन के मध्य 16वें दौर की वार्ता

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्न पत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- भारत और चीन के मध्य सैन्य स्तर की वार्ता का 16वां दौर भारत की ओर चुशुल-मोल्डो स्थल में आयोजित की गई।
- ज्ञातव्य है कि यह बैठक विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इंडोनेशिया के बाली में जी-20 देशों के विदेशमंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर चीन के विदेशमंत्री वांग यी के साथ हुई बैठक के बाद आयोजित की गई है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

केन्द्रित बिन्दु

- आयोजित बैठक नें मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों से सेना हटाए जाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।
- विदित है कि भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के मध्य आखिरी दौर की वार्ता 11 मार्च को हुई थी।

भारत की मांग

- भारत ने चीन पर दबाव डाला कि वह पूर्वी लद्दाख के विवाद वाले क्षेत्रों से सेना को पूरी तरह पीछे हटाए।
- दोनों देशों के बीच करीब चार महीने के अंतराल के बाद वार्ता का दौर फिर शुरू हुआ है।
- वार्ता में भारतीय पक्ष ने सीमा पर अप्रैल 2020 में सैन्य झड़प आरंभ होने से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की।
- 16वें दौर की वार्ता के दौरान, भारत ने चीन से पूर्वी लद्दाख में दो घर्षण बिंदुओं पर अपनी अग्रिम-तैनात सैनिकों और तंबुओं को वापस लेने की मांग की।
- विदित है कि चीन ने देप्सांग मैदानी क्षेत्र, पीपी-15, चार्डिंग-निंग्लुंग नाला क्षेत्र में और डेमचोक के दक्षिण के बीच जो घुसपैठ की थी, उस पर काबिज है।
- भारत ने चीन पर घर्षण बिंदुओं के करीब लड़ाकू विमानों के उड़ान का मुदा उठाया।
- चीनी लड़ाकू विमानों में से एक ने 28 जून को एक घर्षण बिंदु पर भारतीय सैन्य ठिकानों पर उड़ान भरी।
- ऐसी संभवना व्यक्त की जा रही थी कि इस वार्ता से हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के पेट्रोलिंग प्वाइंट 15 पर सैन्य तैनाती घटाने की दिशा में प्रगति हो सकती है।

गत सैन्य वार्ताएं

- दोनों देशों के मध्य 15वें दौर की सैन्य वार्ता 11 मार्च को हुई थी। यद्यपि, इसमें विवाद सुलझाने को लेकर कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी।
- भारत और चीन की सेनाओं के मध्य 14वें दौर की वार्ता में कोई सफलता नहीं मिली और दोनों पक्ष सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों से करीबी संपर्क बनाए रखने और शेष मुद्दों के यथाशीघ्र "परस्पर स्वीकार्य समाधान" के लिए वार्ता जारी रखने को सहमत हुए।

पृष्ठभूमि

- सैन्य और कूटनीतिक वार्ता की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने गत वर्ष पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे और गोगरा क्षेत्र में अलगाव की प्रक्रिया पूरी की थी।
- पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद 5 मई, 2020 को भारत और चीन की सेनाओं के बीच पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद शुरू हुआ था।

- विदित है कि इसके बाद से दोनों देशों ने भारी भरकम हथियारों के साथ ही 50,000 से 60,000 सैनिकों की तैनाती की हुई है।

समाधान

- चीनी घुसपैठ और पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के लगभग दो साल होने जा रहे हैं।
- बफर ज़ोन (मुख्यतः एलएसी के अंदर भारतीय क्षेत्र में) के साथ सेनाओं की वापसी गलवान नदी, पैंगोंग त्सो के उत्तर तथा दक्षिण और गोगरा/चांगलुंग नाला क्षेत्रों से हो चुकी है, जिसमें कोई गश्ती न करने, सेना की कोई तैनाती न करने और इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास न करने की व्यवस्था शामिल है।

स्रोत: द हिन्दू

कृषि ऋण माफी योजनाएं

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** आर्थिक मुद्दे

संदर्भ

- हाल ही में, भारतीय स्टेट बैंक के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2014 के बाद से नौ राज्यों द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी के इच्छित लाभार्थियों में से केवल आधे को ही वास्तव में ऋण माफी मिली है।

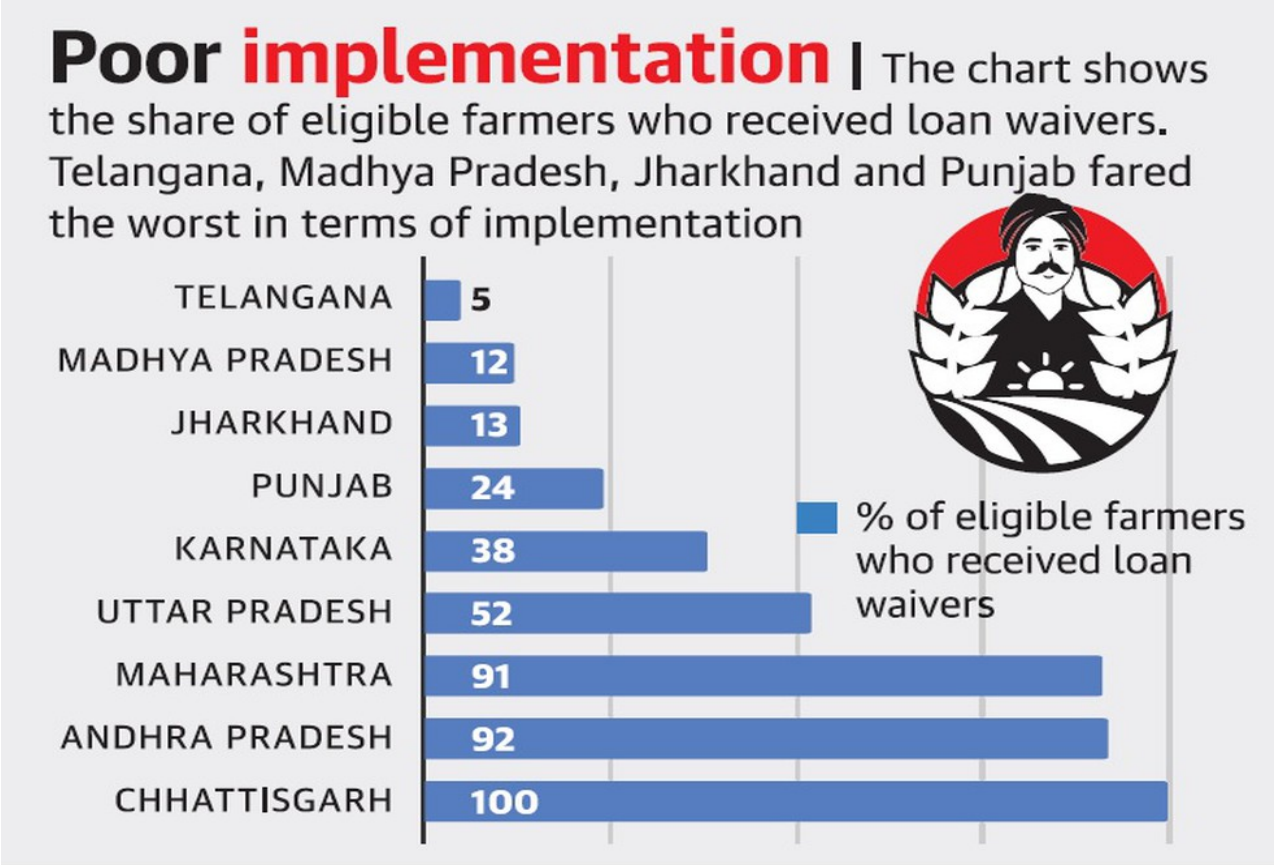

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- मार्च 2022 तक, घोषित लाभ प्राप्त करने वाले पात्र किसानों के अनुपात के संदर्भ में कृषि ऋण माफी योजनाओं का सबसे खराब कार्यान्वयन तेलंगाना (5%), मध्य प्रदेश (12%), झारखंड (13%), पंजाब (24 %), कर्नाटक (38%) और उत्तर प्रदेश (52%) में था।
- इसके विपरीत, 2018 में छत्तीसगढ़ और 2020 में महाराष्ट्र द्वारा लागू की गई कृषि ऋण माफी क्रमशः 100% और 91% पात्र किसानों द्वारा प्राप्त की गई थी।
- एसबीआई के शोधकर्ताओं का मानना है कि इसी तरह की छूट की घोषणा महाराष्ट्र ने 2017 में 67 लाख किसानों के लिए 34,000 करोड़ रुपये की थी, जिसे 68% लाभार्थियों के लिए लागू किया गया है।
- एसबीआई का अध्ययन वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से शुरू होकर नौ राज्यों द्वारा घोषित लगभग 2.53 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 10 कृषि ऋण बट्टे खाते में डालने के परिणामों पर आधारित था।

संभावित कारण

- रिपोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा किसानों के दावों की अस्वीकृति, वादों को पूरा करने के लिए सीमित या कम वित्तीय स्थिति और बाद के वर्षों में सरकारों में बदलाव, इन ऋण माफी की कम कार्यान्वयन दर के संभावित कारणों के रूप में पहचान की गई है।
- उधारकर्ताओं द्वारा समय पर सेवित ऋण, जो कृषि ऋण माफी द्वारा कवर किए गए थे- झारखंड (100%), उत्तर प्रदेश (96%), आंध्र प्रदेश (95%), पंजाब (86%) और तेलंगाना (84%) में बहुत अधिक थे।
- यद्यपि, महाराष्ट्र में 2020 में घोषित ऋण माफी प्राप्त करने वाले किसानों में से केवल 43% और कर्नाटक में 46% किसानों ने 2018 में 44,000 करोड़ की ऋण माफी योजना प्राप्त की, जिनके पास मानक खाते थे।

निष्कर्ष

- रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि ऋण माफी "ऋण संस्कृति" को नष्ट कर देती है, जो मध्यम से लंबी अवधि में किसानों के हितों को प्रभावित कर सकती है।
- यह कृषि बुनियादी ढांचे में उत्पादक निवेश बढ़ाने के लिए सरकारों के वित्तीय स्थिति को भी सीमित कर सकती है।

स्रोत: द हिन्दू

सिंधुध्वज

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** रक्षा

संदर्भ

- स्वदेशीकरण की ध्वजवाहक नौसेना की किलो क्लास पनडुब्बी आईएनएस सिंधुध्वज को 35 वर्ष की सेवा के बाद विशाखापत्तनम में सेवामुक्त कर दिया गया।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

- जून 1987 में नौसेना में शामिल सिंधुध्वज 1986 और 2000 के बीच रूस से भारत द्वारा अधिग्रहित 10 किलो-श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक थी।
- विदित है कि इनमें से आईएनएस सिंधुरक्षक अगस्त 2013 में मुंबई बंदरगाह में एक दुर्घटना में नष्ट हो गई थी, जबकि सिंधुवीर को स्थानांतरित कर दिया गया था।
- नौसेना के उप-सतह बेड़े में अब सात रूसी किलो-श्रेणी की पनडुब्बियां, चार जर्मन एचडीडब्ल्यू पनडुब्बियां, चार फ्रांसीसी स्कॉर्पीन पनडुब्बियां और स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत शामिल हैं।
- स्कॉर्पीन श्रेणी की अंतिम दो पनडुब्बियां परीक्षण और आउटफिटिंग के विभिन्न चरणों में हैं।

सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बियां

- सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बियां रूस और भारत के मध्य हुए समझौते के तहत बनी हैं, जिनका उपयोग भारतीय नौसेना करती है।
- डीजल-बिजली चलित पनडुब्बियों की विस्थापन क्षमता 3000 टन है।
- इसकी अधिकतम गहराई 300 मीटर एवं अधिकतम गति 18 नॉट है।
- 53 नाविकों के साथ यह 45 दिन तक अकेले संचालन कर सकती है।
- पनडुब्बी के शिखर पर एक ग्रे रंग की शार्क को दर्शाया गया है।
- विदित है कि नौसेना में अपनी पूरी यात्रा के दौरान रूस निर्मित सिंधुघोष श्रेणी की यह पनडुब्बी स्वदेशीकरण की दिशा में भारतीय नौसेना के प्रयासों की ध्वजवाहक थी।
- इन पनडुब्बियों में पहली बार स्वदेशी सोनार, स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुक्मणी, जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और स्वदेशी टॉरपीडो फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया था। पनडुब्बी आईएनएस सिंधुध्वज (एस-56) ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल के साथ सफलतापूर्वक यात्रा पूरी की है। इसे 12 जून 1987 को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था।

भारत में पनडुब्बियों क्षमता

- वर्तमान में, भारत में 15 पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, जिन्हें एसएसके के रूप में वर्गीकृत किया गया है और एक परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, जिसे एसएसबीएन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- एसएसके में से, चार शिशुमार क्लास हैं, जिन्हें 1980 के दशक में जर्मनों के सहयोग से भारत में खरीदा और बनाया गया था।
- आठ किलो क्लास या सिंधुघोष क्लास हैं, जिन्हें 1984 और 2000 के बीच रूस (पूर्व सोवियत संघ सहित) से खरीदा गया था और तीन कलवरी क्लास स्कॉर्पीन पनडुब्बी हैं, जिन्हें फ्रांस के नेवल ग्रुप, जिसे पहले डीसीएनएस कहा जाता था, के साथ साझेदारी में भारत के मझगांव डॉक पर बनाया गया था।
- भारत की अधिकांश पनडुब्बियाँ 25 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, जिनमें से कई का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

भारत के पनडुब्बी अधिग्रहण का इतिहास

- भारत को अपनी पहली पनडुब्बी, जो फॉक्सटोर्ट क्लास की आईएनएस कलवरी थी, वह दिसंबर 1967 में यूएसएसआर से मिली थी।
- 1971-74 के बीच भारत ने चार फॉक्सटोर्ट क्लास पनडुब्बी खरीदी।
- 1981 में पश्चिम जर्मनी के साथ दो टाइप 209 पनडुब्बी खरीदने का करार हुआ, वहीं दो अन्य को मेझगांव डॉक पर असेंबल किया गया. यह शिशुमार क्लास थी, जिन्हें पहली बार 1986 में कमीशन किया गया था।
- उसी दौरान रूस ने भारत को किलो क्लास पनडुब्बी देने का प्रस्ताव दिया।
- 1986 से 1992 के बीच भारत ने यूएसएसआर से 8 पनडुब्बी और दो जर्मनी से प्राप्त की।
- 1992 और 1994 के बीच दो जर्मन पनडुब्बी भारत में बनाई गई थी, उन्हें भी कमीशन किया गया, इस तरह 1986 से आठ साल के अंदर 12 नई पनडुब्बी भारतीय बेड़े में शामिल हुई।
- 1995 तक भारत विश्व में सबसे आधुनिक पनडुब्बी वाले देशों में शामिल था।

भारत में पनडुब्बियों का आधुनिकीकरण

- 1999 में सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति की स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण की 30 वर्षीय योजना में, विदेशी ओरिजिनल इक्यूपमेंट मैनुफेक्चरर (ओईएम) के साथ भारतीय साझेदारी में दो उत्पादन लाइन निर्माण की योजना थी, जिनमें से प्रत्येक में 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जाना था। विदित है कि इस परियोजना को पी-75 और पी-75आई नाम दिया गया था।
- इस 30 वर्षीय योजना में यह अनुमान व्यक्त किया गया था कि 2012-15 तक भारत के पास 12 नई पनडुब्बी होंगी।
- इसी तरह 2030 तक भारत 12 और पनडुब्बी का निर्माण कर लेगा और भारत के बेड़े में 24 नई पनडुब्बियाँ होंगी।

स्रोत: द हिन्दू